



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी, 2015

(17 माघ, 1936 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013 (2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 32) (केवल हिन्दी में)	3—11
भाग-II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं	
भाग-IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	शुद्धि पर्ची संख्या 178 रूल्ज/II. डी4, दिनांक 29 जनवरी, 2015	1

Price : Rs. 5.00

(vi)

भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 फरवरी, 2015

संख्या लैज. 40/2014—दि हरियाणा प्रॉट्रैक्शन ऑव इन्ड्रिस्ट ऑव डिपॉजिट्स इन फाइ-नैन्शेल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट, 2013, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 29 जनवरी, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

2014 का हरियाणा अधिनियम संख्या 32

हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013

वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण

करने के लिए तथा उनसे सम्बन्धित या

उनसे आनुषंगिक मामलों हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा वित्तीय स्थापना में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन नियुक्त किया गया प्राधिकारी;
 - (ख) "निक्षेप" में किसी वित्तीय स्थापना द्वारा धन की कोई प्राप्ति या किसी मूल्यवान वस्तु की स्वीकृति चाहे नकदी में या किसी भी प्रकार से या विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या किसी अन्य रूप में किसी लाभ सहित या के बिना विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा वापस किया जाना शामिल है तथा सदैव शामिल की गई समझी जायेगी, किन्तु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है—
 - (i) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का केन्द्रीय अधिनियम 15), के अधीन जारी किए गये मार्गदर्शनों तथा बनाये गये विनियमों के अधीन आने वाली शेयर पूंजी के रूप में या ऋणपत्र, बन्धपत्र या किसी अन्य दस्तावेज के रूप में जुटाई गई राशि;
 - (ii) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में अभिदाय की गई राशि;
 - (iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 5 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित

किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त की गई राशि;

(iv) निम्नलिखित से प्राप्त की गई कोई राशि —

(I) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ;

(II) राज्य वित्तीय निगम ;

(III) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) की धारा 4क में विनिर्दिष्ट कोई वित्तीय संस्था; या

(IV) कोई अन्य संस्था जो इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये ;

(v) निम्नलिखित के रूप में कारबार के साधारण अनुक्रम में प्राप्त की गई राशियाँ —

(I) प्रतिभूति निक्षेप ;

(II) व्यवहारी निक्षेप ;

(III) अग्रिम धन ; या

(IV) माल या सेवाओं हेतु मांग पर अग्रिम ;

(vi) राज्य में तत्समय लागू साहूकारी से सम्बन्धित किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत वैयक्तिक या फर्म या व्यष्टि-संगम जो निगमित निकाय नहीं है, से प्राप्त की गई कोई राशि;

(vii) चिट के सम्बन्ध में अंशदानों के रूप में प्राप्त की गई कोई राशि।

व्याख्या.— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, “चिट” का वही अर्थ होगा, जो चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (1982 का केन्द्रीय अधिनियम 40), की धारा 2 के खण्ड (ख) में इसे निर्दिष्ट किया गया है ; तथा

(viii) किसी सम्पत्ति (चाहे चल या अचल) के विक्रय पर क्रेता को किसी विक्रेता द्वारा दिया गया कोई ऋण;

(ग) “पदाभिहित न्यायालय” से अभिप्राय है, धारा 9 के अधीन गठित न्यायालय;

(घ) “वित्तीय स्थापना” से अभिप्राय है, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के अधीन पंजीकृत वैयक्तिक, व्यष्टि-संगम, फर्म या कम्पनी या सीमित देनदारी भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन पंजीकृत सीमित देनदारी भागीदारी जो किसी स्कीम या प्रबन्धन के अधीन या किसी अन्य रीति में निक्षेप स्वीकार करती है, किन्तु इसमें किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन निगम या सहकारी सोसाइटी या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन यथा परिभाषित बैंकिंग कम्पनी शामिल नहीं है;

(ड) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

3. (1) कोई वित्तीय स्थापना जो निक्षेप या ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या यथा वचनबद्ध किसी अन्य रूप में लाभ का पुनः भुगतान करने में चूक करती है या ऐसे निक्षेप के प्रति वचनबद्ध कोई विनिर्दिष्ट सेवा देने में असफल रहती है, या किसी व्यक्ति को अनुचित अभिलाभ पहुंचाने के आशय से निक्षेप के विरुद्ध सहमति के अनुसार कोई विशिष्ट सेवा देने में असफल रहती है या दूसरे व्यक्ति की सदोष हानि करती है या अव्यवहार्य से उत्पन्न इसकी असमर्थता के कारण ऐसी चूक करती है या ऐसा निक्षेप स्वीकार करते समय किए गए वचन के अनुसार वाणिज्य की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है या धन के परिनियोजन से उत्पन्न या ऐसी रीति में निक्षेपों में से अर्जित परिसम्पत्तियां जब आवश्यक हों, उन्हें वसूल करने में अन्तर्निहित जोखिम अन्तर्ग्रस्त है, कपटपूर्ण रूप से की गई चूक समझी जाएगी या विशिष्ट सेवा देने में असफल रही समझी जाएगी।

वित्तीय स्थापना द्वारा कपटपूर्ण चूक।

(2) यदि कोई वित्तीय स्थापना ब्याज, बोनस, लाभ के रूप में या यथा वचनबद्ध किसी अन्य रूप में किसी लाभ सहित परिपक्वता पर निक्षेप के किसी पुनः भुगतान करने में चूक करती है या निक्षेप के प्रति दिए गए आश्वासन के अनुसार सेवा देने में असफल रहती है, तो ऐसी वित्तीय स्थापना के प्रबन्धन या कारबार या कार्यकलापों के संचालन के लिए उत्तरदायी प्रोत्साहक, भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक या किसी अन्य व्यक्ति या किसी कर्मचारी सहित प्रत्येक व्यक्ति, कारावास की ऐसी अवधि से जो सात वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से जो दो लाख रुपए तक हो सकता है, दण्डित होगा। ऐसी वित्तीय स्थापना जुर्माना जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा या जहां ऐसा निक्षेप धन के रूप में कपटपूर्ण राशि से अनुमान्य दोगुना है, जो भी अधिक हो, के लिए भी दायी होगी :

परन्तु अभिलिखित विशेष तथा पर्याप्त कारणों के अभाव में, जहां तक प्रत्येक व्यक्ति का सम्बन्ध है कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होगा तथा जुर्माना जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा ऐसी वित्तीय स्थापना के प्रति दो लाख रुपए से कम नहीं होगा।

4. (1) तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी,—
- (i) जहां निक्षेपक या अन्यथा से प्राप्त की गई शिकायत पर, जिला मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि हो जाती है कि कोई वित्तीय स्थापना —
 - (क) परिपक्वता के बाद या निक्षेपक द्वारा मांग करने पर निक्षेप वापिस करने में असफल रहती है; या
 - (ख) ब्याज या अन्य सुनिश्चित लाभ का भुगतान करने में असफल रहती है; या
 - (ग) ऐसे निक्षेप के विरुद्ध वचनबद्ध सेवा उपलब्ध करवाने में असफल रहती है; या
 - (ii) जहां जिला मजिस्ट्रेट के पास विश्वास करने का कारण है कि कोई वित्तीय स्थापना निक्षेपक को प्रवंचित करने के आशय से उनके हितों के लिए हानिकार संगणित रीति में कार्य कर रही है तथा यदि जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी वित्तीय स्थापना के लिए निक्षेप वापस करना अथवा ब्याज या अन्य आश्वासित लाभों का भुगतान करना या सेवाएं, जिनके विरुद्ध निक्षेप प्राप्त किया गया है, उपलब्ध करवाना संभाव्य नहीं

निक्षेप की वापसी की चूक पर सम्पत्तियों की कुर्की।

है, तो जिला मजिस्ट्रेट, ऐसी वित्तीय स्थापनाओं के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से, सुनवाई का अवसर देने तथा कारणों को अभिलिखित करने के बाद, वित्तीय स्थापना द्वारा संगृहीत निक्षेपों से तथा में से ऐसी वित्तीय स्थापना चाहे उसके अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से संबंधित या द्वारा अर्जित करने के लिए माने गए धन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों की कुर्की के लिए राजपत्र में इसे प्रकाशित करते हुए आदेश जारी कर सकता है या यदि यह प्रकट होता है कि ऐसा धन या अन्य सम्पत्ति या परिसम्पत्तियां कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं हैं या निक्षेपों के पुनः भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो उक्त वित्तीय स्थापना की ऐसी अन्य सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों या उक्त वित्तीय स्थापना के प्रोत्साहकों, भागीदारों, निदेशकों, प्रबन्धकों, सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की वैयक्तिक परिसम्पत्तियों के कुर्की के आदेश कर सकता है जैसा जिला मजिस्ट्रेट ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश के प्रकाशन पर, वित्तीय स्थापना तथा उसमें वर्णित व्यक्तियों के नाम से सभी धन, सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियां पदाभिहित न्यायालय से लम्बित आगामी आदेश तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में तुरन्त निहित होंगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, जिला मजिस्ट्रेट अपनी रिपोर्ट सहित ऐसी शिकायत सरकार को शीघ्र भेजेगा तथा अन्वेषण के लिए जिले में सम्बद्ध पुलिस अधीक्षक को शिकायत की प्रति भेजेगा।

(4) कुर्की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5) के अधीन डिक्री के निष्पादन में सम्पत्ति की कुर्की हेतु उपबन्धित रीति में की जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी
की नियुक्ति।

5. जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी करते समय धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क किए गए धन तथा सम्पत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकता है जो सहायक कलक्टर प्रथम ग्रेड की पदवी से नीचे का न हो।

सक्षम प्राधिकारी
के कर्तव्य तथा
शक्तियां।

6. (1) नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी धारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्क किए गए सम्बद्ध वित्तीय स्थापना के सभी धन, सम्पत्तियां तथा परिसम्पत्तियों का भौतिक कब्जा लेने के लिए ऐसे आवश्यक कदम, जो वह आवश्यक या समीचीन समझे, उठाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उक्त आदेश के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर, आधार जिन पर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 4 के अधीन उक्त आदेश जारी किया है तथा ऐसे आगामी आदेशों के लिए जो पदाभिहित न्यायालय ठीक समझे धन की राशि या अन्य सम्पत्तियां या परिसम्पत्तियां जो निक्षेपों से सम्बन्धित हों या में से अर्जित की गई मानी गई हों तथा व्यक्तियों के ब्यौरे, यदि कोई हों, जिनके नाम ऐसी सम्पत्ति धारा 4 के अधीन विनिहित की गई या अर्जित की गई या कुर्क की गई कोई अन्य सम्पत्ति मानी गई हो, अभिव्यक्त करते हुए एक या अधिक शपथ-पत्रों के साथ पदाभिहित न्यायालय को आवेदन करेगा।

(3) उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन निहित पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी —

(क) किसी पुलिस प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति की सहायता ले सकता है तथा ऐसी अपेक्षा पर, पुलिस प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति का आवश्यक सहायता देने का कर्तव्य होगा;

(ख) किसी अनुसूचित बैंक में खाते खुलवा सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपनी हैसियत में प्राप्त किए गए धन का संव्यवहार करते समय वसूल किए गए सभी धन जमा करवा सकता है तथा बैंक खाते का संचालन कर सकता है;

(ग) वित्तीय स्थापना के किसी धन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों पर कब्जा या नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति को आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने या ऐसे धन, सम्पत्ति तथा परिसम्पत्तियों का कब्जा सुपुर्द करने तथा ऐसे व्यक्ति को तुरन्त निर्देशों की अनुपालना करने के लिए निदेश दे सकता है;

(घ) विधि व्यवसायी या चार्टर्ड एकाउंटेंट या कोई अन्य व्यक्ति जिनकी सेवाएं वित्तीय स्थापना की परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और वसूली करने के लिए आवश्यक हैं, को नियुक्त कर सकता है; तथा

(ङ) पदाभिहित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार बैंक खाते से भुगतान कर सकता है।

(4) सक्षम प्राधिकारी उस न्यायालय या किसी न्यायिक फोरम, जैसी भी स्थिति हो, की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अवस्थित किसी वित्तीय स्थापना से सम्बन्धित धन या सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित मामले के किसी विवाद या विषय को न्यायनिर्णीत करने हेतु किसी समरूप अधिनियमिति के अधीन किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित या शक्तियों से न्यस्त किसी न्यायालय या किसी अन्य न्यायिक फोरम में समुचित आदेश पारित करवाने हेतु आवेदन भी कर सकता है।

परिसम्पत्तियों तथा निक्षेप दायित्वों का निर्धारण।

7. (1) नियुक्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर, सक्षम प्राधिकारी वित्तीय स्थापना के निक्षेप दायित्वों तथा परिसम्पत्तियों का निर्धारण करेगा तथा पदाभिहित न्यायालय को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी उसके बाद या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रभावी मीडिया प्रकाशन के द्वारा, प्रतिभूत लेनदार, यदि कोई हो, के दावों को आमंत्रित करते हुए तथा वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों को भी दावों को सिद्ध करने हेतु उचित सबूत सहित उनके दावों को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करेगा।

(3) उप धारा (2) के अधीन दावाकर्ताओं को भेजे गये या प्रभावी किये गये, समझे गये प्रत्येक नोटिस में अभिव्यक्त किया जाएगा कि यदि दावे का विवरण नोटिस

की तिथि से एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा गया है, तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(4) प्रतिभूत लेनदार को भेजे गये प्रत्येक नोटिस में नोटिस की तिथि से एक मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व उससे प्रतिभूति के मूल्य की अपेक्षा करेगा तथा ऐसे नोटिस में यह भी अभिव्यक्त करेगा कि यदि प्रतिभूति के मूल्यांकन के साथ-साथ दावे का विवरण सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी प्रतिभूति का मूल्यांकन करेगा तथा ऐसा मूल्यांकन बाध्यकारी होगा।

सक्षम प्राधिकारी
द्वारा रिपोर्ट।

8. धारा 7 के अधीन रिपोर्ट करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी वसूल किए गए धन में से निक्षेपकों को भुगतान करने की अनुज्ञा मांगते हुए पदाभिहित न्यायालय को आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन करते समय, सक्षम प्राधिकारी निक्षेपकों के दायित्व तथा अन्य दायित्वों का निर्धारण करेगा तथा यदि कुर्क किया गया या वसूलीयोग्य धन सम्पूर्ण दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो निक्षेपकों को भुगतान करने के लिए पदाभिहित न्यायालय से अनुज्ञा मांगते हुए अनुरोध करेगा तथा पदाभिहित न्यायालय के आदेशों के अनुसार धन का वितरण करेगा।

पदाभिहित
न्यायालय।

9. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सरकार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी या वर्ग के लिए अपर जिला न्यायाधीश सहित जिला न्यायाधीश के संवर्ग में एक या अधिक पदाभिहित न्यायालय गठित कर सकती है।

(2) पदाभिहित न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय को जो किसी मामले के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों का अवलंब लेता है, अधिकारिता नहीं होगी।

(3) किसी अन्य न्यायालय में लम्बित कोई मामला जिसको इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं, उप धारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की तिथि से पदाभिहित न्यायालय को अन्तरित हो जाएगा।

कुर्की से संबंधित
पदाभिहित
न्यायालय की
शक्ति।

10. (1) धारा 6 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, पदाभिहित न्यायालय, वित्तीय स्थापना या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति धारा 4 के अधीन कुर्क की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी में निहित है, आवेदन, शपथ-पत्रों तथा अन्य साक्ष्य, यदि कोई हो, द्वारा संलग्न नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि को या से पूर्व उक्त स्थापना या व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न कुर्की का स्पष्ट आदेश किया जाए, अभिलिखित करते हुए नोटिस जारी करेगा।

(2) पदाभिहित न्यायालय, इसको प्रतिवेदन करने वाले सभी अन्य व्यक्तियों जो वित्तीय स्थापना की सम्पत्ति में कोई हित रखते हैं या हक रखते हैं या हक होने की सम्भावना का दावा करने या उन व्यक्तियों जिनको उपधारा (1) के अधीन नोटिस जारी किया जाता है, नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट उसी तिथि को उपस्थित होने के लिए ऐसे सभी व्यक्तियों से अपेक्षा करते हुए तथा सम्पत्ति या उसके किसी भाग की कुर्की के सम्बन्ध में इस आधार पर कि वे ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग में हित रखते हैं, कोई आक्षेप, यदि वे ऐसा चाहते हैं, करते हैं, को भी ऐसा नोटिस जारी करेगा।

(3) कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, किसी बात के होते हुए भी कि उस पर इस धारा के अधीन कोई नोटिस तामील नहीं किया गया है, उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है, से पूर्व विनिर्दिष्ट तिथि को या से पहले किसी भी समय पदाभिहित न्यायालय को यथापूर्वोक्त कोई आक्षेप कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तिथि को या से पूर्व कोई हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है और कोई आक्षेप नहीं किया जाता है, तो पदाभिहित न्यायालय कुर्की के स्पष्ट आदेश करते हुए तुरन्त आदेश पारित करेगा, तथा कुर्क परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए तथा इस प्रकार वसूल किए गए धन से तथा कुर्क की गई सम्पत्ति में से निक्षेपकों के बीच उचित वितरण करने के लिए यथा आवश्यक ऐसा निदेश जारी करेगा।

(5) यदि यथापूर्वोक्त कोई हेतुक दर्शाया जाता है या कोई आक्षेप किया जाता है, तो पदाभिहित न्यायालय, उसका अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होगा और ऐसा करने में पक्षकारों के ब्यान लेने के सम्बन्ध में और सभी अन्य प्रकार से पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन यथा अपेक्षित संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, तथा वाद की सुनवाई में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। आक्षेप करने वाले किसी व्यक्ति से साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा की जाएगी कि कुर्की की तिथि को उसका इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति में कोई हित था।

(6) उपधारा (5) के अधीन अन्वेषण के बाद, पदाभिहित न्यायालय इसको मामले के प्रेषण के अधिमानतः एक वर्ष के भीतर, यथाशीघ्र सम्भव, या तो धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए कुर्की के स्पष्ट आदेश करते हुए या कुर्की से सम्पत्ति के भाग की वसूली द्वारा इसमें हेर-फेर करते हुए या कुर्की के आदेश को रद्द करते हुए आदेश पारित करेगा :

परन्तु पदाभिहित न्यायालय उपधारा (1) में निर्दिष्ट वित्तीय स्थापना या व्यक्ति जो सम्पत्ति में कोई हित रखता है, कुर्की से तब तक निर्मुक्त नहीं करेगा जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है कि कुर्की के अधीन किसी राशि या सम्पत्ति का मूल्य ऐसे मूल्य से कम नहीं होगा जो ऐसी वित्तीय स्थापना के निक्षेपकों को पुनः भुगतान करने के लिए अपेक्षित है।

(7) जहां पदाभिहित न्यायालय उपधारा (6) के अधीन कुर्की के स्पष्ट आदेश करते हुए या कुर्की से सम्पत्ति के किसी भाग को निर्मुक्त करते हुए कुर्की के आदेश में हेर-फेर करते हुए कोई आदेश पारित करता है, तो यह कुर्क की गई परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए तथा इस प्रकार वसूल किए गए धन से तथा कुर्क की गई परिसम्पत्तियों में से निक्षेपकों के बीच उचित वितरण के लिए यथा आवश्यक ऐसे निदेश जारी कर सकता है।

11. (1) जहां धारा 4 में निर्दिष्ट वित्तीय स्थापना या अन्य व्यक्ति की कुर्की हेतु उपलब्ध परिसम्पत्तियां, ऐसी राशि या मूल्य से कम की पाई जाती हैं जो ऐसी वित्तीय स्थापना से निक्षेपकों को पुनः भुगतान करने के लिए अपेक्षित हैं तथा जहां पदाभिहित न्यायालय शपथ-पत्र या अन्यथा से संतुष्ट हो जाता है कि उसके विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण हैं कि उक्त वित्तीय स्थापना ने सद्भावपूर्वक और सप्रतिफल से भिन्न किसी भी सम्पत्ति का अन्तरण (चाहे इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व या बाद में)

असद्भावपूर्वक
अन्तरितियों की
सम्पत्ति की कुर्की।

किया है, तो पदाभिहित न्यायालय, नोटिस द्वारा, ऐसी सम्पत्ति (चाहे उसने उक्त वित्तीय स्थापना से सम्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की है या नहीं) के किसी अन्तरिती से नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि को उपस्थित होने तथा कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि क्यों न अन्तरिती की सम्पत्ति के लगभग उतने को ही कुर्क कर दिया जाए जो अन्तरित की गई सम्पत्ति के उचित मूल्य के बराबर है।

(2) जहां उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट तिथि को उपस्थित नहीं होता है तथा कारण नहीं बताता है, या जहां धारा 10 की उपधारा (5) में उपबन्धित रीति में अन्वेषण के बाद, पदाभिहित न्यायालय की संतुष्टि हो जाती है कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अन्तरण सद्भावपूर्वक और सप्रतिफल नहीं था, तो पदाभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की सम्पत्ति के लगभग उतने की ही कुर्की के आदेश करेगा जो पदाभिहित न्यायालय की राय में अन्तरित की गई सम्पत्ति के उचित मूल्य के बराबर हो।

कुर्की के बदले में प्रतिभूति।

12. कोई वित्तीय स्थापना या व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई है या कुर्क की जाने के दायरे में है, किसी भी समय, पदाभिहित न्यायालय को ऐसी कुर्की के बदले में प्रतिभूति देने की स्वीकृति के लिए आवेदन करेगा तथा जहां पदाभिहित न्यायालय की राय में प्रस्तावित तथा दी गई प्रतिभूति, सन्तोषजनक तथा पर्याप्त है, तो वह, यथास्थिति, कुर्की के आदेश को रद्द करेगा या कुर्की के स्पष्ट आदेश करने से विरत रहेगा।

कुर्क की गई सम्पत्ति का प्रशासन।

13. पदाभिहित न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई तथा सक्षम प्राधिकारी में निहित किसी सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर तथा सक्षम प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो पदाभिहित न्यायालय निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त समझे—

(क) इस प्रकार कुर्क तथा सक्षम प्राधिकारी में निहित ऐसी सम्पत्ति से जिसका आवेदक ऐसी राशियों में हित का दावा करता है जो आवेदक तथा उसके परिवार के भरणपोषण के लिए तथा आवेदक की प्रतिरक्षा से सम्बन्धित खर्चों, जहां धारा 3 के अधीन दाण्डिक कार्यवाहियां पदाभिहित न्यायालय में उसके विरुद्ध संस्थित की गई हैं, के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हैं, उपलब्ध करवाना;

(ख) जहां तक व्यवहार्य हो कुर्की से प्रभावित किसी कारबार के हित तथा विशेषतः ऐसे कारबार में किन्हीं भागीदारों के हित को सुरक्षित रखना।

अपील।

14. यदि सक्षम प्राधिकारी सहित कोई व्यक्ति, पदाभिहित न्यायालय के आदेश से व्यथित है, तो आदेश की तिथि से साठ दिन के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकता है।

विशेष लोक अभियोजक।

15. सरकार, अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित न्यायालय में मामले के संचालन के प्रयोजन के लिए बार में कम से कम दस वर्ष के स्थाई अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक या विशेष सरकारी प्लीडर के रूप में नियुक्त करेगी।

अपराधों के बारे पदाभिहित न्यायालय की प्रक्रिया तथा शक्तियां।

16. (1) पदाभिहित न्यायालय विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किए बिना अपराध का संज्ञान ले सकता है तथा अभियुक्त व्यक्ति का विचारण करते समय, सत्र

मामलों के विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), में विहित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), के सभी उपबन्ध, जहां तक हो सके, पदाभिहित न्यायालय के सम्मुख कार्यवाहियों को लागू होंगे तथा उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय के रूप में समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

17. इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय लागू किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रिवाज या किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभाव रखेंगे।

अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना।

18. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सक्षम प्राधिकारी या सरकार के अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

19. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

20. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी कोई भी बात कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

रमेन्द्र जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।